Madhya Pradesh. According to available information, out of these 36 licences, one licence was granted for the manufacture of items pertaining to food processing industries in the cooperative sector.

Hike in the prices of Nickel, Tin and Zinc

1328. PROF. C. LAKSHMANNA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that MMTC, which is a canalising agency, has hiked the prices of nickel, tin and zinc;

(b) if so, what would be its impact on industries which use these basic metals; and

(c) what are the reasons for this increase ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES AND THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE) : (a) to (c) The domestic selling prices of nickel, tin and zinc are fixed every month by a Pricing Committee under the Chairmanship of Chief Controller of Imports & Exports after taking into account the landed cost of imports by Minerals and Metals Trading Corporation Limited (MMTC), the canalising agency, with the prevailing import duties added. Thus, any increase in the international prices of these metals has a direc bearing on the domestic prices.

The prices of these non-ferrous metals since January, 1989 are indicated below ;

Rs. per MT

	Nickel	Tin	Zinc
January '89	3,54,000	2,52,000	39,800
February '89	3,75,000	2,52,000	42,500
March '89	4,08,000	2,65,000	48,200
April '89	4,23,000	2,96,000	50,500
May '89	4,23,000	3.88,000	50,500

The prices of these non-ferrous metals have a bearing on the cost of production of manufactured goods to the extent of their use.

Decontrol of Steel

1329. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under Government's consideration to decontrol steel; and

(b) if so, at what stage does it rest now ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES AND THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

1330. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों के संबंध में मंडल आयोग के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट अन्य

पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों के लिए आरक्षण करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय मत प्राप्त करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और करने का विचार रखती है, और

(ख) सिफारिशों को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) और (ख) सरकार का यही मत रहा है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर तब तक यथास्थिति बनाई रखी जाय जब तक कि राष्ट्रीय मतैक्य नहीं हो जाता ।

बंजारा को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना

1331. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक शिष्ट मंडल ने हाल ही में प्रधान मंत्री से भेंट की थी और मांग की थी कि सभी ग्वार बंजारा को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित किया जाए ; और

(ख) क्या इस मांग के समर्थन में 10 अप्रैल, 1989 को दिल्ली में एक रैली की गई थी; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) अखिल भारतीय बंजारा सम्मेलन के एक शिष्टमंडल ने 5-4-1989 को प्रधान मंत्री से भेंट की थी और बंजारों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की थी ।

(ख) 11-4-89 को समाचार पत्रों में बताया गया है कि 10-4-1989 को इंडिया गेट के लान में काफी संख्या में बंजारों द्वारा रैली आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने अपनी जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की थी । संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है । इस स्तर पर और आगे जानकारी नहीं बताई जा सकती ।

District Forum and State Commission constituted under Consumer Protection Act

1332. SHRI KAILASH PATI MISHRA : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) the name and complete address of each District Forum and State Commission which has started functioning along with the jurisdiction area of each such district forum under Consumer Protection Act;

(b) the name, address and qualifications of each member of District Forum/State Commission approved by Government till date; and

(c) the names and addresses of each laboratory which has been recognised under Consumer Protection Act till date alongwith products which can be tested at each laboratory ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Government has not recognised any laboratory under section 2(1) a of the Consumer Protection Act, 1986. However, laboratories set up by or under any law for the time being in force, as defined in